

फ्रैंक विटस

बनाम

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व अन्य

(आपराधिक अपील सं. 2814-2815/2024)

08 जुलाई 2024

[न्या. अभय एस. ओका* एवं न्या. उज्ज्वल भुइयां]

विचारणीय विवादक

अपीलार्थी को उक्त आदेश में शामिल विभिन्न नियमों एवं शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता जमानत देते समय लगाई गई दो शर्तों से व्यथित है। ये दो शर्तें इस प्रकार हैं: (i) नाइजीरिया के उच्चायोग से आश्वासन का प्रमाण पत्र अभिलेख पर रखा जाना चाहिए कि आवेदक/आरोपी देश नहीं छोड़ेंगे तथा जब भी आवश्यकता होगी विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होंगे; (ii) आरोपी को यह सुनिश्चित करने के लिए गूगल मैप पर एक पिन डालना होगा कि उसका स्थान मामले के जांच अधिकारी को उपलब्ध है।

शीर्ष टिप्पणियां

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 21 - स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - जमानत में नियम व शर्तें - गूगल मैप पर पिन डालने की एक शर्त:

अभिनिर्धारित: शपथपत्र में, गूगल एलएलसी ने कहा कि उपयोगकर्ता के पास अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ पिन साझा करने का पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा, यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर कोई अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि उपयोगकर्ता के पास पूरा नियंत्रण रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिन स्थान उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के डिवाइस की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम नहीं करता है। अतः, आरोपी द्वारा गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप की शर्त, जैसा कि यह है, पूरी तरह से निरर्थक है क्योंकि यह प्रथम प्रत्यर्थी की मदद नहीं करता है। - जमानत पर कोई भी शर्त लगाना जो पुलिस/जांच एजेंसी को किसी भी

तकनीक का उपयोग करके या अन्यथा ज़मानत पर रिहा किए गए अभियुक्त की हर गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है, निस्संदेह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगी। - इस मामले में, पिन ड्रॉप के तकनीकी प्रभाव और ज़मानत की शर्त के रूप में उक्त शर्त की प्रासंगिकता पर विचार किए बिना ही गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप की शर्त को शामिल किया गया है। - यह ज़मानत की शर्त नहीं हो सकती है। - इस शर्त को हटाया जाना चाहिए और तदनुसार आदेश दिया जाना चाहिए। [पैरा 10.1, 10.2]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - जमानत में नियम व शर्तें - दूतावास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त:

अभिनिर्धारित: यह आवश्यक नहीं है कि हर मामले में जहां एनडीपीएस मामले में किसी विदेशी नागरिक को न्यूनतम सजा के 50% से अधिक लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत दी जाती है, दूतावास/उच्चायोग से 'आश्वासन का प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की शर्त को शामिल किया जाना चाहिए। - यदि ऐसी शर्त शामिल की गई है, तो भी अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, संबंधित दूतावास/उच्चायोग उचित समय के भीतर, जैसे कि सात दिनों की अवधि के भीतर, प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर देता है या विफल रहता है, न्यायालय के पास हमेशा उक्त शर्त को समाप्त करने का अधिकार है। दूतावास/उच्चायोग द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र प्रदान करना उस अभियुक्त के नियंत्रण से परे है, जिसे जमानत दी गई है। अतः, जब दूतावास/उच्चायोग उचित समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो अभियुक्त, जिसे अन्यथा जमानत का हकदार माना जाता है, को इस आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है कि ऐसी शर्त, जिसका पालन करना अभियुक्त के लिए असंभव है, का पालन नहीं किया गया है। अतः, न्यायालय को शर्त हटानी होगी। यदि दूतावास/उच्चायोग प्रमाण पत्र अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करता है और कारण सामग्री के आधार पर अभियुक्त के प्रतिकूल आचरण पर आधारित हैं, तो न्यायालय शर्त को समाप्त करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय हमेशा दर्ज किए गए कारणों पर विचार कर सकता है। हालांकि, न्यायालयों को यह याद रखना चाहिए कि अभियुक्त को दूतावास/उच्चायोग को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिकूल रूप से दर्ज करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो फिर से पहले से दी गई जमानत को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो

सकते हैं। ऐसे मामले में, इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त के बजाय, पासपोर्ट को सरेंडर करने और नियमित रूप से स्थानीय पुलिस स्टेशन/विचारण न्यायालय में रिपोर्ट करने की शर्त हमेशा लगाई जा सकती है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। - तदनुसार, वर्तमान मामले में दूतावास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की उक्त शर्त को हटाने का आदेश दिया जाता है। [पैरा 11.1, 12]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 37 और धारा 52 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 437(3) – एनडीपीएस के तहत की गई गिरफ्तारियों पर दं.प्र.सं. का अनुप्रयोग:

अभिनिर्धारित: एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत, न्यायालय की जमानत देने की शक्ति उप-धारा 1(ख)(ii) द्वारा बाधित है। हालाँकि, एक बार धारा 37 के अनुसार जमानत देने का मामला बन जाने पर, जमानत की शर्तें दं.प्र.सं. की धारा 437(3) के अनुसार होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के कारण, दं.प्र.सं. के प्रावधान एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं, जब तक कि वे एनडीपीएस अधिनियम के साथ असंगत न हों। [पैरा 4.1]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 437(3) – “न्यायिक हित” शब्दों का अर्थ:

अभिनिर्धारित: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(3) में “न्यायिक हित” शब्दों को व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त भाषा को उधार लेकर हम कह सकते हैं कि जमानत की शर्तें काल्पनिक, मनमानी या विचित्र नहीं हो सकती हैं। जमानत की शर्तें लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त किसी भी तरह से जांच में हस्तक्षेप या बाधा न डाले, जांच के लिए उपलब्ध रहे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट न करे, कोई अपराध न करे, विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहे और मुकदमे के शीघ्र समापन में बाधा उत्पन्न न करे। न्यायालयों ने शर्त लगाई है कि अंतिम रिपोर्ट या आरोपपत्र दाखिल करने से पहले जमानत दिए जाने पर अभियुक्त को जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच में सहयोग करने का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त को स्वीकार करना ही होगा। जमानत देने के आदेश में शामिल शर्तें धारा 437(3) के दायरे में होनी चाहिए। जमानत की शर्तें लगाने के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। जमानत की शर्तें लगाते समय, जमानत पर रिहा होने का

आदेश पाने वाले अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों को केवल न्यूनतम सीमा तक ही सीमित किया जा सकता है। यहां तक कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए और जेल में सजा काट रहे अभियुक्त को भी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके सभी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 7]

उद्धृत निर्णय विधि

कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य (2018) 16 एससीसी 74; मुनीश भसीन बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) [2009] 2 एससीआर 806 : (2009) 4 एससीसी 45; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी [2000] 3 एससीआर 644 : (2000) 5 एससीसी 712 - पर भरोसा किया गया।

विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ व अन्य [1994] पूरक 4 एससीआर 386 : (1994) 6 एससीसी 731; तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य [2020] 12 एससीआर 583 : (2021) 4 एससीसी 1 - से संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; जमानत में नियम व शर्तें; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(3); स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(3) में "न्यायिक हित" शब्दों का अर्थ; जमानत में गूगल मानचित्र पर पिन छोड़ने की शर्त; जमानत में दूतावास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त; भारत के संविधान में अनुच्छेद 21; गोपनीयता का अधिकार।

से उद्धृत मामले

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 2814-2815/2024,

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बीए संख्या 4187/2020 के दिनांक 31.05.2022 व 18.08.2022 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर उपस्थितियां

वरुण मिश्रा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्याय मित्र।

विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी., वेंकट रघु वामसी दासिका, उपेन्द्र मिश्रा, राहुल जी तनवानी, प्रसेनजीत महापात्र, अरविंद कुमार शर्मा, गुरुमीत सिंह मक्कड़, प्रशांत रावत, अद्वितिया अवस्थी, अनिरुद्ध शर्मा-द्वितीय, अशोक पाणिग्रही, राज बहादुर यादव, अभिषेक सिंह, एम/एस ट्राइलीगल एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, लज़फ़ीर अहमद बी.एफ., अनुज बेरी, सुश्री अनुषा रमेश, सुश्री करिश्मा सुंदरा, अपराजिता सेन, सुश्री मुस्कान वाधवा, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

न्या. अभय एस. ओका,

1. अनुमति प्रदानित।

तथ्यात्मक पहलू

2. अपीलार्थी पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एतद्पश्चात् 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 8, 22, 23 एवं 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजित किया जा रहा है। अपीलार्थी को दिनांक 21 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 31 मई 2022 के पहले आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलार्थी को उक्त आदेश में शामिल विभिन्न नियमों व शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। शामिल नियम व शर्तें इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में अपने निर्णय के पैराग्राफ सं. 15 में जारी निर्देशानुसार थीं। अपीलार्थी को एनडीपीएस के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि में दो जमानतदारों के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।
3. इस अपील में शिकायतों को इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21 जुलाई 2023 के आदेश में संक्षेपित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“याचिकाकर्ता जमानत देते समय लगाई गई निम्नलिखित शर्तों से व्यथित है:

“.. विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, एससी सं. 27/14 में वाद की सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि नाइजीरिया के उच्चायोग से आश्वासन का प्रमाण पत्र अभिलेख पर रखा जाए कि आवेदक/अभियुक्त देश नहीं छोड़ेंगे तथा जब भी आवश्यक हो, विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होंगे, क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8/22/23/29 के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई शिकायत से संकेत मिलता है कि अपीलार्थीगण नाइजीरिया के निवासी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ

[(1994) 6 एससीसी 731] के मामले में खंड (iv) इस प्रकार है:

“(iv) ऐसे विचाराधीन अभियुक्तों के मामले में जो विदेशी हैं, विशेष न्यायाधीश उनके पासपोर्ट जब्त करने के अलावा, उस देश के दूतावास/उच्चायोग से आश्वासन प्रमाणपत्र पर जोर देंगे, जिसका विदेशी अभियुक्त निवासी है, कि उक्त अभियुक्त देश नहीं छोड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;”

प्रथम दृष्टया, हमारा मानना है कि कोई भी दूतावास/उच्चायोग खंड (iv) में उल्लिखित आश्वासन देने में सक्षम नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि क्या हमें खंड (iv) पर पुनर्विचार के लिए इस मामले को एक वृहद न्यायपीठ को भेजने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई एक अन्य शर्त इस प्रकार है:

“... उन्हें गूगल मैप पर एक पिन डालना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका स्थान मामले के जांच अधिकारी को उपलब्ध है;...”

प्रश्न यह है कि क्या यह शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करेगी।

हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवरे से अनुरोध करते हैं कि वे दोनों मुद्दों पर न्यायमित्र के रूप में हमारी सहायता करें। रजिस्ट्री को वरिष्ठ अधिवक्ता को पेपर बुक का पूरा सेट तथा इस आदेश की एक प्रति उपलब्ध करायें।

दिनांक 14.08.2023 को सूचीबद्ध।”

- 3.1 हमने न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवरे, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण मिश्रा एवं प्रथम प्रत्यर्थी-नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना है।

जमानत की शर्तें

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.')
- की धारा 439 सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने की शक्ति से संबंधित है। हम तैयार संदर्भ हेतु धारा 439 को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

“439 :- जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ - (1) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त, जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए:

परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास के दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है।

[यह भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारतीय दंड संहिता (45/1860) की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376-कख या धारा 376-घक या धारा 376-घख के अधीन विचारणीय अपराध का अभियुक्त है, जमानत देने से पूर्व, जमानत के लिए आवेदन की सूचना ऐसे आवेदन की

सूचना प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।]

[(1-क) भारतीय दंड संहिता (45/1860) की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376-कख या धारा 376-घक या धारा 376-घख के तहत व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचना देने वाले या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।]

(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तथा उसे हिरासत में लिया जाये।”

धारा 437(3) इस प्रकार है:

“437. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी-

(1)

(2)

(3) जब कोई व्यक्ति, जो सात वर्ष या उससे अधिक तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने का या भारतीय दंड संहिता (45/1860) के अध्याय VI, अध्याय XVI या अध्याय XVII के अधीन अपराध करने का या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न का अभियुक्त है या संदिग्ध है, उपधारा (1) के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है, तब [न्यायालय निम्नलिखित शर्तें लगाएगा,—

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा,

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसका उस पर संदेह है, या जिसके करने का उस पर संदेह है, तथा

(ग) ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके,

तथा न्यायिक हित में ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।]

(4)

- 4.1** इस मामले में, हम एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित हैं, जिसके लिए सात साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। जमानत से संबंधित प्रावधान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित है, जो इस प्रकार है:

“37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।—

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) किसी व्यक्ति पर धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-क के तहत दंडनीय अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी आरोपी को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि-

(i) सरकारी अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, तथा

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) या जमानत देने पर वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।]”

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत, न्यायालय की जमानत देने की शक्ति उप-धारा 1(ख)(ii) द्वारा बाधित है। हालाँकि, एक बार धारा 37 के अनुसार जमानत देने का मामला बन जाने पर, जमानत की शर्तें दं.प्र.सं. की धारा 437(3) के अनुसार होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के कारण, दं.प्र.सं. के प्रावधान एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं, जब तक कि वे एनडीपीएस अधिनियम के साथ असंगत न हों।

5. दं.प्र.सं. की धारा 437(3) में शर्तों (क) से (ग) के अलावा, "न्यायिक हित में" अतिरिक्त शर्तें लगाने की शक्ति है। दं.प्र.सं. की धारा 437(3) में "न्यायिक हित" की अवधारणा के दायरे पर इस न्यायालय ने **कुणाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य** के मामले में विचार किया है। पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"9. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 437(3) का खंड (ग) न्यायालयों को न्यायिक हित में ऐसी शर्तें लगाने की अनुमति देता है। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से ऐसे शब्द व्यापक अर्थ को स्वीकार करने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसी शर्तें मनमानी, काल्पनिक या प्रावधान के उद्देश्यों से परे नहीं हो सकती हैं। धारा 437(3) के खंड (ग) के तहत प्रयोग किए गए "न्यायिक हित" वाक्यांश का अर्थ है "न्याय का सुप्रशासन" या "परीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना" और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के कारण व्यापक अर्थ को शामिल करने से बचना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

6. दं.प्र.सं. की धारा 438(2)(iv) के मद्देनजर, अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 437(3) में दी गई शर्तों को लागू करने का अधिकार है। अग्रिम जमानत देते समय लगाई जा सकने वाली शर्तों से निपटान के दौरान, इस न्यायालय ने **मुनीश भसीन बनाम राज्य (रा.रा.क्ष. दिल्ली)** के मामले में इस प्रकार निर्णय दिया:

"10. यह बात सर्वविदित है कि धारा 438 के तहत किसी आरोपी को रिहा करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय न तो उच्च न्यायालय और न ही सत्र न्यायालय को विचित्र शर्तें लगाने का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय धारा 438 के तहत किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय आवश्यक, न्यायसंगत और प्रभावी शर्तें लगा सकता है। हालांकि, आरोपी पर किसी भी तरह की अप्रासंगिक शर्त नहीं लगाई जा सकती है।"

(जोर दिया गया)

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(3) में "न्यायिक हित" शब्दों को व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त भाषा

को उधार लेकर हम कह सकते हैं कि जमानत की शर्तें काल्पनिक, मनमानी या विचित्र नहीं हो सकती हैं। जमानत की शर्तें लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त किसी भी तरह से जांच में हस्तक्षेप या बाधा न डाले, जांच के लिए उपलब्ध रहे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट न करे, कोई अपराध न करे, विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहे और मुकदमे के शीघ्र समापन में बाधा उत्पन्न न करे। न्यायालयों ने शर्त लगाई है कि अंतिम रिपोर्ट या आरोपपत्र दाखिल करने से पहले जमानत दिए जाने पर अभियुक्त को जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच में सहयोग करने का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त को स्वीकार करना ही होगा। जमानत देने के आदेश में शामिल शर्तें धारा 437(3) के दायरे में होनी चाहिए। जमानत की शर्तें लगाने के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। जमानत की शर्तें लगाते समय, जमानत पर रिहा होने का आदेश पाने वाले अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों को केवल न्यूनतम सीमा तक ही सीमित किया जा सकता है। यहां तक कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए और जेल में सजा काट रहे अभियुक्त को भी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके सभी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने, [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी](#) के मामले में, निम्नलिखित निर्णय देकर स्थापित स्थिति को दोहराया:

“22. जीवन का अधिकार मूल मानवाधिकारों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को इसकी गारंटी दी गई है और राज्य को भी इस अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। एक कैदी, चाहे वह दोषी हो, विचाराधीन हो या बंदी हो, इंसान नहीं रह जाता है। कारागार में बंद होने पर भी, वह संविधान के तहत उसे दिए गए जीवन के अधिकार सहित अपने सभी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना जारी रखता है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से वंचित होने पर, कैदियों के पास अभी भी संवैधानिक अधिकारों का अवशेष बना रहता है।”

(जोर दिया गया)

7.1. हम एक ऐसे आरोपी के मामले का निपटान कर रहे हैं जिसका अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है। जब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक निर्दोष होने का अनुमान लागू होता है। उसे अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके सभी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालयों को जमानत की शर्तें लगाते समय संयम दिखाना चाहिए। अतः, जमानत देते समय, न्यायालय केवल विधि द्वारा वारंट की गई जमानत शर्तों को लागू करने के लिए आवश्यक सीमा तक ही आरोपी की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। जमानत की शर्तें इतनी कठोर नहीं हो सकतीं कि जमानत के आदेश को ही विफल कर दें। उदाहरण के लिए, न्यायालय समय-समय पर पुलिस स्टेशन/न्यायालय में रिपोर्ट करने या बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा न करने की शर्त लगा सकता है। जहां परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्षी या पीड़ितों की सुरक्षा के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने से आरोपी को रोकने की शर्त लगा सकता है। लेकिन न्यायालय आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आवाजाही के बारे में पुलिस को लगातार सूचित करता रहे। जमानत की शर्त का उद्देश्य जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना नहीं हो सकता है। जांच एजेंसी को जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की निजी जिंदगी में लगातार झांकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह मनमानी शर्तें लगाकर ऐसा कर सकता है, क्योंकि इससे आरोपी के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 21 में दी गई है। अगर जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की हर हरकत पर तकनीक या किसी और तरीके से लगातार नजर रखी जाती है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के निजता के अधिकार सहित गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसकी वजह यह है कि जमानत पर रिहा किए गए आरोपी पर इस तरह की लगातार निगरानी रखने का असर यह होगा कि जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसे किसी तरह की कैद में रखा जाएगा। ऐसी शर्तें जमानत की शर्तें नहीं हो सकती हैं।

8. दं.प्र.सं. की धारा 441 की उपधारा (2) के मद्देनजर, जमानत देते समय न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तें हमेशा आरोपी द्वारा निष्पादित जमानत बांड में शामिल होती हैं। अतः, आरोपी जमानत देते समय लगाई गई शर्तों से बंधा हुआ है। यदि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है, तो न्यायालयों के पास हमेशा जमानत रद्द करने का अधिकार होता है।
9. जमानत देते समय ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती जिसका पालन करना आरोपी के लिए असंभव हो। अगर ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं तो इससे आरोपी को जमानत से वंचित होना पड़ेगा, हालांकि वह इसके लिए हकदार है।

गूगल मैप पर पिन ड्रॉप करने की स्थिति

10. सबसे पहले, हम गूगल मैप्स पर पिन डालने की शर्त के मुद्दे पर विचार करेंगे। गूगल मैप पर पिन डालने की अपीलार्थी पर लगाई गई शर्त से यह आभास होता है कि यह शर्त प्रथम प्रत्यर्थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को वास्तविक समय के आधार पर अभियुक्तों की गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम बनाएगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। “गूगल मैप पर पिन ड्रॉप” के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए, हमने गूगल एलएलसी को एक नोटिस जारी किया, जिसका कार्यालय यूएसए में है। तदनुसार, गूगल एलएलसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री आर. सुरेश बाबू ने एक शपथपत्र दायर किया है। उनके शपथपत्र के पैराग्राफ 5 से 10 इस प्रकार हैं:

“5. गूगल मैप्स एक वेब और ऐप-आधारित सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को स्थानीय स्थानों को खोजने और नेविगेट करने में सक्षम बनाती है। यह अन्य बातों के अलावा वास्तविक समय की ट्रैफ़िक स्थिति और पैदल, कार, बाइक, हवाई और सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा के लिए मार्ग नियोजन प्रदान करता है। गूगल मैप्स को मोबाइल पर उपलब्ध गूगल मैप्स एप्लिकेशन या www.google.com/maps पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

6. गूगल मैप्स पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं में से एक यह है कि उपयोगकर्ता मानचित्र पर अपनी पसंद के स्थान पर ‘पिन’ डाल सकते हैं। पिन डालने से उपयोगकर्ता मानचित्र पर किसी स्थान को चिह्नित या पहचान सकता है, इसके लिए उपयोगकर्ता के स्थान डेटा तक पहुँच की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोगकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन या वेब ब्राउज़र पर पिन डाल सकते हैं। पिन डालने के लिए, उपयोगकर्ता निम्न में से कोई एक कर सकता है:

क. मोबाइल एप्लिकेशन पर मानचित्र पर उस इच्छित स्थान को दबाकर रखें जहाँ पिन डालना है; या

ख. वेब ब्राउज़र पर मानचित्र पर इच्छित स्थान पर क्लिक करें।

7. पिन डालने पर, पिन डालने वाला उपयोगकर्ता मानचित्र पर स्थान के विशिष्ट निर्देशांक की पहचान कर सकता है। गूगल मैप्स ऐप या वेब ब्राउज़र के माध्यम से, पिन डालने वाला उपयोगकर्ता

स्थान के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त करने, स्थान को लेबल से चिह्नित करने, स्थान पर व्यवसाय का पता जोड़ने या किसी अन्य उपयोगकर्ता के साथ स्थान साझा करने का विकल्प चुन सकता है।

8. पिन, गूगल मैप्स पर उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए किसी विशिष्ट स्थान की पहचान करता है और उसे चिह्नित करता है। पिन को उस स्थान पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां पिन साझा करते समय उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता का डिवाइस स्थित है। पिन साझा करने वाले उपयोगकर्ता का वास्तविक समय का स्थान होना आवश्यक नहीं है।

9. गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं को तीसरे पक्ष के साथ पिन जैसी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। यह गूगल की गोपनीयता नीति में समझाया गया है, जो <https://policies.google.com/privacy?hl=en-US> पर उपलब्ध है, और इस प्रकार साझा करता है: "हमारी कई सेवाएं आपको अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा करने देती हैं, और **आपके पास साझा करने के तरीके पर नियंत्रण होता है** [जोर दिया गया]।"। जब वे गूगल अकाउंट बनाते हैं तो उपयोगकर्ता गोपनीयता नीति से सहमति देते हैं। इस मामले में, यदि कोई उपयोगकर्ता पिन साझा करना चाहता है, तो वे 'शेयर' बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। यह गूगल मैप्स के लिए एक लिंक उत्पन्न करता है जिसे उपयोगकर्ता मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म या ऑनलाइन संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से दूसरों के साथ साझा कर सकता है। जब क्लिक किया जाता है, तो लिंक उपयोगकर्ताओं (लिंक तक एक्सेस रखने वाले) को उस स्थान पर निर्देशित करता है जहां पिन मानचित्र पर ड्रॉप किया गया था।

10. गूगल मैप्स पिन सुविधा, जिसमें पिन बनाना या किसी अन्य उपयोगकर्ता के साथ ऐसे पिन को साझा करना शामिल है, उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर कोई अतिक्रमण नहीं करती है क्योंकि उपयोगकर्ता के पास ऐसी जानकारी साझा करने पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लिंक तक पहुँच रखने वाला उपयोगकर्ता केवल गूगल मैप्स पर पिन किए गए और साझा किए गए स्थिर स्थान तक ही पहुँच सकता है। **पिन किए गए स्थान से उपयोगकर्ता या उनके डिवाइस की वास्तविक समय ट्रैकिंग संक्षम नहीं होती है।** भले ही पिन किसी निश्चित समय पर उपयोगकर्ता के स्थान से

मेल खाता हो, यह (क) उपयोगकर्ता द्वारा पिन किया गया स्थिर स्थान होगा; और (ख) केवल तभी दूसरों के लिए सुलभ होगा जब कोई उपयोगकर्ता शेयर बटन पर क्लिक करके पिन को उनके साथ सकारात्मक रूप से साझा करेगा।”

(जोर दिया गया)

- 10.1.** शपथपत्र के पैराग्राफ 10 में, गूगल एलएलसी ने कहा कि उपयोगकर्ता के पास अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ पिन साझा करने का पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा, यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर कोई अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि उपयोगकर्ता के पास पूरा नियंत्रण रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिन स्थान उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के डिवाइस की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम नहीं करता है। अतः, आरोपी द्वारा गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप की शर्त, जैसा कि यह है, पूरी तरह से निरर्थक है क्योंकि यह प्रथम प्रत्यर्थी की मदद नहीं करता है।
- 10.2.** ज़मानत पर कोई भी शर्त लगाना जो पुलिस/जांच एजेंसी को किसी भी तकनीक का उपयोग करके या अन्यथा ज़मानत पर रिहा किए गए अभियुक्त की हर गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है, निस्संदेह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगी। इस मामले में, पिन ड्रॉप के तकनीकी प्रभाव और ज़मानत की शर्त के रूप में उक्त शर्त की प्रासंगिकता पर विचार किए बिना ही गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप की शर्त को शामिल किया गया है। यह ज़मानत की शर्त नहीं हो सकती है। इस शर्त को हटाया जाना चाहिए और तदनुसार आदेश दिया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, इस न्यायालय ने इसी तरह की शर्त लगाई हो सकती है। लेकिन उन मामलों में, इस न्यायालय को ऐसी शर्त के प्रभाव और वैधता के मुद्दे पर निर्णय करने के लिए नहीं बुलाया गया था।

द्रुतावास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त

- 11.** अब हम [**सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति**](#) के उस निर्णय पर आते हैं जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है। पैराग्राफ 15 के पहले भाग में इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में की गई प्रार्थनाओं को बताया गया है। हम पैराग्राफ 15 के प्रासंगिक भाग को उद्धृत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है:

“15. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायक संस्था को यह याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करने वाला मुख्य कारण विदेशियों से

जुड़े अधिनियम के तहत मामलों के निपटान में देरी थी। दावा की गई राहतों में विदेशियों की आगामी अभिरक्षा को अमान्य मानने का निर्देश शामिल था, जो अधिनियम के तहत दो साल से अधिक अवधि के लिए विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में सड़ रहे थे, या किसी भी मामले में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए तथा अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनके मामलों को दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब याचिका स्वीकार करने के लिए आई तो अधिवक्ता को बताया गया कि समान स्थिति वाले विचाराधीन कैदियों के बीच ऐसा घृणित अंतर जो इस देश के नागरिक हैं और जो विदेशी हैं, संविधान के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकता है तथा भले ही विदेशियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए, इसका प्रभाव यह हो सकता है कि विदेशियों को कतार में आगे निकलने और नागरिकों के मामलों को नीचे खिसकाने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही उनके मामले पुराने हों और लंबे समय से लंबित हों। अधिवक्ता ने तुरंत महसूस किया कि अगर ऐसा अंतर किया जाता है तो इसका परिणाम विदेशियों के इशारे पर भारतीय नागरिकों के मामलों में और देरी होगी, एक ऐसी प्रक्रिया जो कानून के अनुरूप नहीं हो सकती है। अतः, उन्होंने याचिका के कारण-शीर्षक और प्रार्थना खंडों में संशोधन करने की अनुमति मांगी, जिसे अनुमति दे दी गई। मूल रूप से याचिकाकर्ता अब प्रार्थना करता है कि सभी विचाराधीन कैदी जो अधिनियम के तहत किसी अपराध या अपराधों के लिए दो साल से अधिक समय से जेल में हैं, उनके खिलाफ दर्ज मामलों के निपटान में देरी के कारण उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए और उनकी आगामी अभिरक्षा को अवैध और शून्य घोषित किया जाना चाहिए और उक्त बड़े मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय तक, उन्हें किसी भी मामले में जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

इसी अनुच्छेद 15 में निर्देश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

“अतः हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

- (i) **जहां विचाराधीन कैदी पर अधिनियम के तहत किसी अपराध का आरोप है, जिसमें पांच वर्ष या उससे कम की सजा और जुर्माना निर्धारित है, ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा किया**

जाएगा, यदि वह उस अवधि के लिए जेल में रहा है, जो उस अपराध के लिए निर्धारित सजा के आधे से कम नहीं है, जिसका उस पर आरोप है और जहां उस पर एक से अधिक अपराधों का आरोप है, तो वह अपराध जो सबसे अधिक सजा का प्रावधान करता है। यदि उस पर आरोपित अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना निर्धारित है, तो जमानत राशि उक्त राशि का 50% होगी, जिसमें समान राशि के दो जमानतदार होंगे। यदि अधिकतम जुर्माना निर्धारित नहीं है, तो जमानत संबंधित विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के अनुसार होगी, जिसमें समान राशि के दो जमानतदार होंगे।

- (ii) जहां विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम के अंतर्गत पांच वर्ष से अधिक की सजा और जुर्माने का प्रावधान करने वाले अपराध का आरोप लगाया गया है, ऐसे विचाराधीन अभियुक्त को उपरोक्त (i) में निर्धारित अवधि पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि उसकी जमानत राशि किसी भी मामले में 50,000 रुपये से कम नहीं होगी और समान राशि के दो जमानतदार होंगे।
- (iii) जहां विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है, जो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, यदि वह कम से कम पांच वर्ष तक जेल में रहा हो, बशर्ते कि वह एक लाख रुपये की जमानत राशि के साथ उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे।
- (iv) जहां किसी विचाराधीन अभियुक्त पर अधिनियम की धारा 31 और 31-क के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है, ऐसा विचाराधीन अभियुक्त इस आदेश के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं होगा।

उपरोक्त खंड (i), (ii) व (iii) में दिए गए निर्देश निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन होंगे:

- (i) जमानत पर रिहा होने का हकदार विचाराधीन अभियुक्त को अपना पासपोर्ट संबंधित विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के पास जमा करना होगा और यदि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वह इस आशय का शपथपत्र उस प्रारूप में दाखिल करेगा जो विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बाद के मामले में, यदि विद्वान विशेष न्यायाधीश के पास बयान की सत्यता पर संदेह करने का कारण है, तो वह संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को बयान को सत्यापित करने के लिए लिखेगा और पासपोर्ट अधिकारी उसके रिकॉर्ड को सत्यापित करेगा और तीन सप्ताह के भीतर जवाब भेजेगा। यदि वह उक्त समय के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो विद्वान विशेष न्यायाधीश विचाराधीन अभियुक्त के बयान पर कार्रवाई करने का हकदार होगा;
- (ii) विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने पर उस पुलिस थाने में, जिसने उस पर वाद चलाया है, उपस्थित होना होगा, जो खंड (i) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के मामले में एक महीने में कम से कम एक बार, खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के मामले में एक पखवाड़े में एक बार और खंड (iii) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के मामले में एक सप्ताह में एक बार, जब तक कि संबंधित विशेष न्यायाधीश से अग्रिम रूप से छुट्टी प्राप्त न कर ली गई हो;
- (iii) खंड (ii) और (iii) में दिए गए निर्देश का लाभ उन अभियुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगा जो, विद्वान विशेष न्यायाधीश की राय में, लिखित रूप में बताए जाने वाले कारणों से, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या अभियोजन पक्ष के साक्षी को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं;
- (iv) ऐसे विचाराधीन अभियुक्तों के मामले में जो विदेशी हैं, विशेष न्यायाधीश उनके पासपोर्ट जब्त करने के अलावा, उस देश के दूतावास/उच्चायोग से

आश्वासन प्रमाणपत्र पर जोर देंगे, जिसका विदेशी-अभियुक्त निवासी है, कि उक्त अभियुक्त देश नहीं छोड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(v) विचाराधीन अभियुक्त विद्वान विशेष न्यायाधीश की अनुमति के बिना उस क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा जिसके संबंध में विशेष न्यायालय गठित किया गया है;

(vi) विचाराधीन अभियुक्त जमानत राशि के बराबर नकद राशि जमा करके जमानत दे सकता है;

(vii) यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है या जमानत रद्द करने का मामला बनता है तो विशेष न्यायाधीश जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे; तथा

(viii) इस आदेश के अनुसरण में विचाराधीन अभियुक्तों की रिहाई के पश्चात्, उन विचाराधीन अभियुक्तों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें रिहा नहीं किया गया है और जो जेल में हैं तथा विशेष न्यायालय उनके साथ संहिता की धारा 309 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(जोर दिया गया)

हालाँकि, अनुच्छेद 16 प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

“16. हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त निर्देशों का उद्देश्य उन मामलों के लिए एक बार के निर्देश के रूप में कार्य करना है जिनमें आरोपी व्यक्ति जेल में हैं और उनके मुकदमों में देरी हो रही है। इनका उद्देश्य अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने के विशेष न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप करना नहीं है। लंबित मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी की शिकायत को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालय उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। विशेष न्यायालय, निर्देशों के बावजूद, जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि पाया जाता है कि आरोपी इसका दुरुपयोग कर रहा है और जमानत रद्द करने के लिए आधार मौजूद हैं। अंत में, हम इस

आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई के मामले में आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं।”

(जोर दिया गया)

11.1. पैराग्राफ 15 में निहित निर्देश एकमुश्त निर्देश के रूप में कार्य करने थे जो केवल उन अभियुक्तों के लंबित मामलों पर लागू थे जो निर्णय की तिथि को जेल में थे। एकमुश्त उपाय के रूप में किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय इन शर्तों को आदेश में शामिल किया जाना आवश्यक था। पैराग्राफ 16 स्पष्ट करता है कि यदि लंबित मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी के संबंध में शिकायत के साथ विशेष न्यायालय में जमानत आवेदन किया जाता है, तो विशेष न्यायालय पैराग्राफ 15 में जो कहा गया है उसके आलोक में जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त होगा। अतः, यह आवश्यक नहीं है कि हर मामले में जहां एनडीपीएस मामले में किसी विदेशी नागरिक को न्यूनतम सजा के 50% से अधिक लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत दी जाती है, दूतावास/उच्चायोग से 'आश्वासन का प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की शर्त को शामिल किया जाना चाहिए।

12. यदि ऐसी शर्त शामिल की गई है, तो भी अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, संबंधित दूतावास/उच्चायोग उचित समय के भीतर, जैसे कि सात दिनों की अवधि के भीतर, प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर देता है या विफल रहता है, न्यायालय के पास हमेशा उक्त शर्त को समाप्त करने का अधिकार है। दूतावास/उच्चायोग द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र प्रदान करना उस अभियुक्त के नियंत्रण से परे है, जिसे जमानत दी गई है। अतः, जब दूतावास/उच्चायोग उचित समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो अभियुक्त, जिसे अन्यथा जमानत का हकदार माना जाता है, को इस आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है कि ऐसी शर्त, जिसका पालन करना अभियुक्त के लिए असंभव है, का पालन नहीं किया गया है। अतः, न्यायालय को शर्त हटानी होगी। यदि दूतावास/उच्चायोग प्रमाण पत्र अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करता है और कारण सामग्री के आधार पर अभियुक्त के प्रतिकूल आचरण पर आधारित हैं, तो न्यायालय शर्त को समाप्त करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय हमेशा दर्ज किए गए कारणों पर विचार कर सकता है। हालांकि, न्यायालयों को यह याद रखना चाहिए कि अभियुक्त को दूतावास/उच्चायोग को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिकूल रूप से दर्ज करने के लिए

बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो फिर से पहले से दी गई जमानत को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामले में, इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त के बजाय, पासपोर्ट को सरेंडर करने और नियमित रूप से स्थानीय पुलिस स्टेशन/विचारण न्यायालय में रिपोर्ट करने की शर्त हमेशा लगाई जा सकती है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

13. मामले के तथ्यों की बात करें तो अपीलार्थी को सबसे पहले इस आधार पर जमानत दी गई है कि अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयानों के आधार पर फंसाया गया है, और इस तरह के बयान इस न्यायालय के [तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य](#) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। अतः, जमानत गुण-दोष के आधार पर भी दी गई है। दूसरे, जमानत [सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति](#) के मामले में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 15 में कही गई बातों पर भी निर्भर करते हुए दी गई है। चूंकि [तूफान सिंह](#) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए जमानत गुण-दोष के आधार पर दी गई थी, अतः उच्च न्यायालय के पास [सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति](#) के मामले में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 15 में शामिल सभी कठोर शर्तें लगाने का कोई कारण नहीं था।
14. अतः, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि [सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति](#) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 15 में शर्त संख्या (iv) पर पुनर्विचार के लिए मामले को एक वृहद न्यायपीठ को भेजना आवश्यक नहीं है।
15. उपरोक्त उल्लिखित दो मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों के आधार पर, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को जमानत देने वाले आदेश में दो शर्तें, अर्थात् दूतावास/उच्चायोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना और गूगल मैप्स का पिन डालना, हटा दी जाएंगी।
16. अपीलार्थी द्वारा अब तक किए गए अनुपालन पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश पारित करने के लिए मामला दिनांक 15 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

मामले का परिणाम: अंतिम आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाये।

अंकित ज्ञान द्वारा शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गयीं

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.